हम आगे बढ़ेंगे

हमारे मुल्क में एक सियासी तब्दीली आई है। हक़ीक़त यह है कि अपने नुमाइन्दे चुनने और अपनी पसन्द की सरकार बनाने का हक़ हिन्दुस्तानी जम्हूरियत की ताक़त की तस्वीर पेश करता है। इस मोड़ पर जिन लोगों ने इक्तेदार हासिल किया है और जिन लोगों ने इक्तेदार खोया है उन दोनों को अवाम के फैसले का एहतेराम करने में काफी आजिज़ी और इन्केसारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए। हक़ीक़त यह है कि इक्तेदार तो अवाम के हाथ में है और उसने यह इक्तेदार नई पार्लियामेण्ट और नई सरकार को सिर्फ पाँच साल के लिए दे दिया है।

कौन जीता ? कौन हारा ?

इन इन्तेख़ाबात में भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई में कौमी जम्हूरी इत्तेहाद(एन. डी.ए.) की जीत का पैमाना खुद उनके हिसाब और उम्मीद से दूर था। तो हक़ीक़त में हारने वाले कौन हैं ? मुत्तहिदा तरक्की पसंद गठजोड़ (यू.पी.ए.) जिस ने लगातार दस सालों तक अवाम को धोखा दिया उसी ने इक्तेदार खोया । यू.पी.ए. सरकार न तो अवाम के लिए मुत्तहिद थी और न अपने अंदर से तरक्की पसन्द थी। पहले से ही कमज़ोर हो चुकीं बाएँ बाजू की पार्टियाँ जो अवाम से दूर हो कर दाईं तरफ जा रही थीं उन को कड़वी शिकस्त इनाम में मिली। वह इलाकाई पार्टियाँ जो दलित और पिछड़े तब्क़ात की तरक्की की विरासत की हमेशा दावा करती थीं उनको उनके रिवायती वोट बैंक ने रद्द कर दिया। यही नहीं बल्कि सेकुलर ताकतें शिकस्त खा गईं। यह मुल्क के सेकुलर उसूलों के लिए एक धक्का भी था। मुस्लिम फिरका जो सब से बड़ी मज़हबी अकल्लियत है उसने भी शिकस्त में अपने हिस्से का मज़ा इस मायने में चखा की जीतने वाली ताकतें उन के शहरी और जम्हूरी हुकूक के अब तक मुखालिफ थीं। हिन्दुस्तान ने हिन्दू फिरका परस्तों के इत्तेहाद और सेकुलर ताकतों और अकल्लियती तबकों के बिखराव का मुशाहिदा किया।

क्यों जीते ? क्यों हारे ?

इन्तेखाबी मुहिम के दौरान विकास का मंत्र बी.जे.पी. के लिए अपने फिरका परस्त एजेंडा को छिपाने के लिए सिर्फ एक मुखौटा था। यह एक ऐसा चुनाव था जो कारपोरेट ग्रुपों की उड़ेली हुई दौलत और अपना दबदबा रखने वाली मीडिया की

हिमायत से लड़ा गया जो कारपोरेट के कंट्रोल में है। लेकिन इस से बढ़ कर बी.जे. पी. की जीत बारीक मंसूबा बंदी, पक्के इरादे से किया गया फील्ड वर्क, लचकदार हिक्मते अमली और असरदार इन्तेखाबी मुहिम का नतीजा थी। वह लोग अलग अलग ग्रुपों को अपना हम नवाँ बनाने के लिए बाहम मुखालिफ पत्ते खेलने में काफी मौका परस्त थे। इनके मुखालिफीन की तरफ से वोटरों ने उलटे ढ़ंग से देखा। कांग्रेस, बाएँ बाजू की पार्टिया और इलाकाई पार्टियाँ ना उम्मीद थीं और इनका कैम्प बटा हुआ था। इनके अन्दर हिक्मते अमली की लचक और इनकी इन्तेखाबी मुहिम असरदार क्या होती इन के अन्दर दूर अंदेशी, हिक्मत और यहाँ जा कि आम समझ भी नहीं थी। ऐसे इन्तेखाबी हल्कों में जहाँ मुसलमान, दलित और पिछड़ी जातियों के वोट फैसला कुन हैं वहाँ इनमें से हर पार्टी ने एक दूसरे के मुकाबले में उम्मीदवार खड़े किए और उन्हों ने अपने वोट बैंक को अपने पसंद के उम्मीद वार को मुत्तहिद होकर चुनने का मौका नहीं दिया। इन हालात में वही हुआ जो हो सकता था।

उम्मीदें और अंदेशे

जम्हूरियत की तारीफ यह ठीक ही की गई है कि यह अवाम की सरकार है जो अवाम के ज़रिये चुनी जाती है जो अवाम के लिए होती है। कोई भी सियासी पार्टी या सियासी इत्तेहाद जब वोट दे कर इक्तेदार की कुरसी पर पहुँचा दिया जाता है तो उसे आईनी गारंटियों जैसे तमाम शहरियों और तबक़ात को इन्साफ, शख्सी और इज्तेमाई आज़ादी, मौकों की बराबरी और अवाम के अंदर भाईचारा और इत्तेहाद को कायम रखते हुए अवाम तक भलाई पहुँचाना और जिम्मेदारी के साथ हुकूमत चलाना होता है। नई सरकार को कारपोरेट दुनिया ने इसे इकतेदार में लाने में जो मदद की थी उसका एहसान चुकाने की मजबूरियों से बाहर निकलना होगा और अवाम के ज़िन्दा मसाइल जैसे भूख, खौफ़, निरक्षरता या ना ख्वांदगी, खराब सेहत और ज़िन्दगी गुज़ारने की खराब सतह को हल करना होगा। सरकार को अकल्लियतों के इन अंदेशों को भी दूर करना होगा कि उन के साथ भेद भाव बरता जाएगा और उन की तहज़ीब और उन के तालीमी हुकूक में कमी की जाएगी।

नई हुकूमत के तहत जो माहौल पैदा किया गया है वह इशारा करता है कि अंदेशे बे बुनियाद नहीं हैं। क़ौमी सलामती और मीडिया के दो अहम सेक्टरों को पूरी तरह

सीधे बेरूनी सरमायाकारी के तहत लाने का सरकार का फैसला क़ौमी सलामती और अवामी राए के दायरों में भी जान बूझ कर समझौता करने की तरफ इशारा करता है। बुनियादी फिरका वाराना मामलों जैसे युनीफार्म सिविल कोड, दफा 370 और राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में संघ परिवार के अलग अलग गुटों की जानिब से जो ग़ैर ज़िम्मेदाराना बयानबाज़ी जारी है उस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। अकल्लियती मामलों की मंत्री ने मज़हबी अकल्लियत के आइनी तसव्वुर पर हि सवाल खड़ा कर दिया है। इससे बढ़ कर नये सियासी इक्तेदार में हिन्दुत्व अनासिर को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फिरका वाराना वारदातें करने के लिए हौसला दे दिया है। बहर हाल पार्लियामेण्ट के दोनों इवानों के मुत्तहिदा इजलास को सरकार की जानिब से जो सद्र जमहूरिया ने खिताब किया उस में यह ठीक ही तसलीम किया गया कि यह बद किस्मती है कि आज़ादी की कई दहाईयों के बाद भी अकल्लियती फिरके के कई तब्कात लगातार गरीबी का शिकार हैं और सरकारी इस्कीमों के फायदे उन तक नहीं पहुँचते। उभरती हुई सूरते हाल नई सरकार के इस वादे का हकीकी इम्तेहान है कि वह हिन्दुस्तान की तरक्की में तमाम अकल्लियतों को बराबर का हिस्सेदार बनाएँगे।

सीट में हिस्सेदारी बनाम वोट की हिस्सेदारी

हालाँकि यह कोई नई सूरते हाल नहीं है फिर भी पिछले चुनाव ने हिन्दुस्तानी इन्तेखाबी निज़ाम की बुनियादी कमी को रोशनी में ला दिया है। खास तौर से कोई खास पार्टी या इत्तेहाद जितनी सीटें हासिल करता है वह उस के हक में डाले गए वोटों के मुतनासिब नहीं होतीं। इन इन्तेखाबात में बी.जे.पी. ने पार्लियामेण्ट की 543 सीटों में से 282 सीटें हासिल कर लीं जब कि उसके हासिल किए हुए वोटों का फीसद सिर्फ 31 है। यह अपने वोटों की हिस्सेदारी की मुनासिबत से सिर्फ 168 सीटों की हकदार है। बहुजन समाज पार्टी के मामले में, जिसने 4.1 फीसद वोट हासिल किया और उसे पार्लियामेण्ट की एक सीट भी नहीं हासिल हुई यह निज़ाम की कमज़ोरी की एक और मिसाल है। यह अपने हासिल वोटों के मुताबिक 22 सीटों की हकदार है। बी.जे.पी. ने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिल कर सिर्फ 38 फीसद वोटरों की हिमायत हासिल की जिस का मतलब यह है कि 62 फीसद लोगों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट दिया है। हकीकत यह है कि मोदी की कयादत में बनने वाली सरकार को यह इम्तेयाज़ हासिल है कि इसने मरकज़ में

बनने वाली किसी भी सरकार से सबसे कम वोट हासिल किया है। यह जीतने वाली पार्टी के लिए एक चेतावनी है कि उसे ज़्यादा खाकसारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए और यह हारने वालों की इक्तेदार में वापसी का एक वादा भी है। लेकिन इस तवाज़ुन की कमी का आखिरी हल हमारे इन्तेखाबी निज़ाम का मुतनासिब नुमाइन्दगी की बुनियाद पर सुधार करना है।

इत्तेहाद में ज़िंदगी है और बिखराव में मौत

इन्तेखाबी नतीजे और उस के बाद उभरने वाली सूरते हाल में तमाम सेकुलर पार्टियों और अकल्लियतों को इमानदारी से अपना हिसाब करने में लग जाना चाहिए। एक मायने में यह ऐसी शिकस्त है जिस के यह हकदार थे क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को नज़र अन्दाज़ किया था। जिन लोगों ने इनको हराया उन से सबक लेने में कोई बुराई नहीं है। सेकुलर पार्टियों के नेताओं और अकल्लियती तन्ज़ीमों को अपनी सोच और तरजीहात में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। उन का फौरी काम यह है कि आने वाले इन्तेखाबात को लड़ने के लिए मंसूबा बंदी के साथ अपनी सियासी बुनियादों को दोबारा हासिल करें और उसे मज़बूत करें। ना इन्साफियों से लड़ने में उन्हें अवाम के दरमियान सबसे आगे रहना चाहिए। उन्हें आपस में मामूली मतभेदों, झूठी शान और अनचाहे मुकाबलों से बचना चाहिए। अगर अभी पिछला तजुरबा सबसे अच्छा टीचर है तो इसका सबक यह है कि इत्तेहाद में ज़िंदगी है और बिखराव में मौत।

चुनौतियों को मौकों में बदलिए

इज़्ज़त के साथ ज़िन्दगी जीने के लिए इज़्ज़ते नफ्स और खुद एतेमादी बुनियादी हैसियत रखती हैं। ख़राब मुस्तकबिल को देख कर ना उम्मीद होने की कोई वजह नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हिन्दुस्तान में वह लोग इक्तेदार में आए हैं जिनका एजेन्डा खास तौर से हिन्दुत्व रहा है। पिछले सालों में जो नाम निहाद सेकुलर सरकारें रहीं हैं उन में भी कबायली लोगों, अकल्लियतों और दलितों को सलामती की ज़िन्दगी नहीं जीने दिया गया। दबे हुए तबकों के लिए यह बहुत अहम मौका है कि वह अपने मक़सद को तय करें, अपने मिशन की मनसूबा बन्दी करें और अपनी ज़िन्दगी अच्छे मुस्तकबिल के लिए लगा दें।

हिन्दुस्तान अपने तमाम शहरियों और तमाम तब्कात की एक जैसी तरक्की चाहता है। हमें सबक लेने के लिए अपने पिछले 66 सालों पर नज़र डालना चाहिए। हमें नई सोच और नए मिशन के साथ अगले 33 सालों पर नज़र रखनी चाहिए।

कोई भी अज़ीम कारनामा चैलेंजों और मुश्किलात से खाली नहीं होता। और हक हासिल करने और निजात के रास्ते में कुरबानियों का कोई मुतबादिल नहीं है।

ना उम्मीदी रखने वाला हर मौके में मुश्किलात देखता है लेकिन उम्मीद रखने वाला इन्सान हर मुश्किल में मौके तलाश करता है।

हर सुरंग के आखिर में रोशनी होती है लेकिन उसे देखने के लिए आप को अपनी आखें खोलनी होंगी।

पापुलर फ्रण्ट आफ इण्डिया
जी –66 तीसरी मंज़िल, शाहीन बाग़ कालिंदी कुंज नोएडा रोड नई दिल्ली–110025